

प्रादेशिक समाचार

जेपी नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज सोलन जिले के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में टेटनस और डिप्थीरिया टीके का शुभारंभ करेंगे। यह टेटनस और डिप्थीरिया जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टेटनस और डिप्थीरिया टीका देश की जन स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काफी अहम है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट

इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का आज आखिरी दिन है। प्रदर्शकों, नवप्रवर्तकों और आगंतुकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार ने एक्सपो को एक दिन और बढ़ा दिया है। एक्सपो सुबह 9 बजकर पंद्रह मिनट से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। एआई इम्पैक्ट समिट को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए आयोजन स्थल ने एक परामर्श जारी किया है। अधिकारियों ने सभी प्रतिभागियों से कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।

समापन

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का समापन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट कई मायनों में सफल रहा है। उन्होंने बताया कि पांच लाख से अधिक लोगों ने इसमें बहुत कुछ सीखा और दुनिया भर के कई विशेषज्ञों से बातचीत की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस आयोजन को बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में विश्व नेताओं ने भाग लिया और मंत्रिस्तरीय स्तर पर दुनिया भर के 45 शिष्टमंडलों ने हिस्सा लिया।

कांग्रेस बैठक

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सहित प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य दिल्ली दौरे पर हैं और बीती शाम नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार अपने स्तर पर भी आर डी

जी की बहाली के लिए लड़ाई जारी रखेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसे बहाल करने की मांग की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस हाईकमान भी इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में हिमाचल के हक की पेरवी करेगा।

बैठक के बाद उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिमाचल को मिलने वाली आरडीजी को बिना किसी पूर्व सूचना के रोका गया है। इससे हिमाचल को हर साल दस हजार करोड़ का नुकसान होगा। अग्निहोत्री ने कहा कि आरडीजी हिमाचल का हक है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल 22 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 131वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़.ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण ए आई आर न्यूज़, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा।

मंडी शिवरात्रि

मंडी में चल रहे अंतरराष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव के तहत भव्य सांस्कृतिक परेड में कल 35 सांस्कृतिक दलों ने भाग लेकर शहर को रंग, संगीत और लोक परंपराओं से सराबोर कर दिया। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय दलों की दमदार भागीदारी महोत्सव की सांस्कृतिक विविधता और वैश्विक सहभागिता का जीवंत उदाहरण बनी। वहीं अंतरराष्ट्रीय दलों ने पारंपरिक लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुख्यातिथि के रूप शिरकत करते हुए कहा कि मंडी का ये अंतरराष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव केवल आस्था का ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता और वैश्विक भाईचारे का भी प्रतीक है।

इस बीच राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होने के लिए आज शाम मंडी पहुंचेंगे और शिवरात्रि महोत्सव की छठी व अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में भाग होंगे।

साइबर सुरक्षा

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि दीर्घकालिक साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागरिक शिक्षा को एक अनिवार्य घटक के रूप में लेना आवश्यक है। वे कल

शाम जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित तीन दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन साइबर सुरक्षा जागरूकता, संरक्षण और न्याय तक समावेशी पहुंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि साइबर सुरक्षा एक सामूहिक प्रतिबद्धता है और सरकार, न्यायपालिका और समाज को इसको पूरा करने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति ने अपार सुविधाएँ प्रदान की हैं। लेकिन, इसका दुरुपयोग एक बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा केवल बैंक खातों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संस्थागत विश्वास की रक्षा करना भी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि न्यायपालिका इस खतरे से निपटने और इसे देश से समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।